



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 27, 2007/आश्विन 5, 1929

No. 287]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2007/ASHWINA 5, 1929

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2007

वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए बोली देने की प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन ।

सं. 23/11/2004-आर एण्ड आर (खण्ड-VI).—1. वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए बोली देने की प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग I, खण्ड 1) में दिनांक 19 जनवरी, 2005 को प्रकाशित संकल्प संख्या 23/11/2004-आर एण्ड आर (खण्ड-II) द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबंधों के अधीन अधिसूचित किया गया था। इन दिशानिर्देशों को दिनांक 30 मार्च, 2006 के राजपत्र संकल्प संख्या 23/11/2004-आर एण्ड आर (खण्ड-IV) तथा दिनांक 18 अगस्त, 2006 की संकल्प संख्या 23/11/2004-आर एण्ड आर (खण्ड-V) द्वारा संशोधित किया गया था।

2. उक्त दिशानिर्देशों में एतद्वारा आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं नामतः :-

2.1 खंड 2.1 के उप-खंड (ख) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाता है :

स्पष्टीकरण : इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ "अधिप्राप्तिकर्ता (अधिप्राप्तिकर्ताओं)" शब्द का अर्थ परिप्रेक्ष्य जैसी अपेक्षा करे, वितरण लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारीगण) अथवा लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारीगण) का प्राधिकृत प्रतिनिधि या बोली प्रक्रिया का कार्य करने के प्रयोजनार्थ गठित विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) होगा। एस.पी.वी. इन दिशानिर्देशों के अनुसार बोली देने की प्रक्रिया के सभी कार्य निष्पादित करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारियों) द्वारा प्राधिकृत भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित एक कंपनी होगी। वितरण लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारीगण) विशेष प्रयोजन साधन को प्रारंभिक परियोजना तैयारी कार्यकलाप (बोली प्रक्रिया पूरी होने के पूर्व किए जाने के लिए प्रस्तावित) भी सौंप सकता है। विशेष प्रयोजन साधन बोली प्रक्रिया के अनुसार चयनित सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किया जा सकेगा।

## 2.2 खंड 2.4 का पहला पैरा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

संयुक्त बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक से अधिक वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अधिप्राप्ति की जा सकेगी और ऐसे मामले में अधिप्राप्तिकर्तागण को किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बोली प्रक्रिया करने का विकल्प होगा। प्राधिकृत प्रतिनिधि अधिप्राप्तिकर्ताओं में से एक अथवा मामला संख्या 2 के लिए ऐसे प्रयोजन के लिए निगमित विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) हो सकता है। ऐसी संयुक्त अधिप्राप्ति के लिए प्रत्येक अधिप्राप्तिकर्ता इन दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आवश्यक सूचना प्रदान करेगा। बोलियों के मूल्यांकन में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अधिप्राप्तिकर्ताओं द्वारा बोलीदाताओं को प्रस्तावित भुगतान सुरक्षा और अन्य वाणिज्यिक शर्तें भिन्न-भिन्न नहीं होंगी। बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित मूल्य भी बोली आमंत्रित करने वाले वितरण लाइसेंसधारियों के लिए समान होगा।

## 2.3 खंड 3.1 (iii) का उप-खंड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

(क) अधिप्राप्त की जाने वाली क्षमता/ऊर्जा की मात्रा के लिए, अगर वह अधिप्राप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित आपूर्ति के प्रत्याशित प्रारंभ के वर्ष के बाद अगले तीन वर्षों के लिए पूर्वानुमानित अतिरिक्त मांग से अधिक होता है। मांग का ऐसा पूर्वानुमान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित अद्यतन उपलब्ध (आरएफक्यू जारी करने के समय) विद्युत शक्ति सर्वेक्षण पर आधारित होगा (मामला संख्या 1 और मामला संख्या 2 दोनों के लिए)।

## 2.4 खंड 3.2 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

3.2 अधिप्राप्त किए जा रहे विद्युत की आपूर्ति सामयिक रूप से प्रारंभ करना सुनिश्चित करने और बोलीदाताओं को अधिप्राप्तिकर्ता के अप्रत्यादेय आशय के बारे में विश्वास दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि परियोजना संबंधी विभिन्न प्रारंभिक कार्यकलाप समय पर पूरे किए जाएं। जल विद्युत परियोजनाओं अथवा उन परियोजनाओं, जिनके लिए पूर्व-अभिज्ञात कार्यस्थलों का उपयोग किया जाना है (मामला संख्या 2), से दीर्घावधिक अधिप्राप्ति के लिए अधिप्राप्तिकर्ता अथवा अधिप्राप्तिकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित मानदंडों का प्रालन करते हुए बोली प्रक्रिया के साथ-साथ परियोजना संबंधी प्रारंभिक कार्यकलाप पूरे किए जाने चाहिए।

(i) कार्यस्थल की पहचान और भूमि अधिग्रहण : अगर विद्युत स्टेशन के लिए भूमि को अधिग्रहित किए जाने की अपेक्षा है तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन आरएफक्यू के प्रकाशन के पूर्व अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अधीन अधिसूचना आरएफपी जारी करने के पूर्व जारी हो जानी चाहिए। अगर आपातस्थिति से संबंधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 के उपबंध लागू नहीं किए गए हैं तो विद्युत क्रय करार (पीपीए) प्रभावी होने के पूर्व भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन निर्णय घोषित हो जाना चाहिए।

(ii) विद्युत स्टेशन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति : तीव्र पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट आरएफक्यू के प्रकाशन के पूर्व उपलब्ध होनी चाहिए। पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए समुचित प्रस्ताव आरएफपी जारी करने के पूर्व केन्द्र/राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, में अंतिम अनुमोदन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो जाना चाहिए। पर्यावरणीय स्वीकृति विद्युत क्रय करार के प्रभावी होने के पूर्व प्राप्त कर ली जानी चाहिए।

(iii) विद्युत स्टेशन हेतु भूमि के लिए वन संबंधी स्वीकृति (अगर लागू हो) : वन संबंधी स्वीकृति के लिए समुचित प्रस्ताव आरएफपी जारी करने के पूर्व केन्द्र/राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, में अंतिम अनुमोदन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो जाना चाहिए।

(iv) ईंधन व्यवस्था : अगर ईंधन लिकेज अथवा कैप्टिव कोयला खान (खानें) प्रदान किए जाने हों तो उन्हें आरएफक्यू के प्रकाशन के पूर्व उपलब्ध होना चाहिए। अगर बोलीदाता से ईंधन की व्यवस्था करने की अपेक्षा की जाती है तो उसे आरएफक्यू में स्पष्टतया निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(v) जल लिकेज : इसे आरएफक्यू के प्रकाशन के पूर्व उपलब्ध होना चाहिए।

(vi) जहां भी लागू हो, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए आवश्यक समुचित जलवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, मौसमवैज्ञानिक और भूकम्पवैज्ञानिक आंकड़े : इन्हें आरएफपी जारी करने के पूर्व उपलब्ध होना चाहिए। बोलीदाता स्वयं अपने संसाधनों के माध्यम से भूवैज्ञानिक आंकड़ों का सत्यापन करने के लिए स्वतंत्र होगा क्योंकि भूवैज्ञानिक जोखिम परियोजना प्रवर्तक पर होगा।

परियोजना कार्यस्थल सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किया जाएगा जिसका मूल्य आरएफपी बोलियों की प्रस्तुति के लिए नियत तारीख के कम से कम 15 दिनों पूर्व सूचित किया जाएगा।

## 2.5 निम्नलिखित खंड 3.4 को खंड 3.3 के नीचे प्रविष्ट किया जाता है :

3.4 मामला संख्या 2 के अधीन परियोजनाओं, जिनसे विभिन्न राज्यों में स्थित एक से अधिक वितरण लाइसेंसधारी एसपीवी के माध्यम से बोली प्रक्रिया पूरी करते हुए विद्युत अधिप्राप्त करने का अभिप्राय रखते हैं, के मामले में विद्युत क्रय करार और अन्य अपेक्षित परियोजना करार (जैसे एस्करो करार, भाराक्रांति करार तथा अन्य परियोजना विशिष्ट करार) इस परन्तुक के साथ कि ये करार सफल बोलीदाता द्वारा एसपीवी के अधिग्रहण की तारीख से लागू होंगे, आरएफपी बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के पूर्व संबंधित पक्षों के बीच किए जा सकते हैं।

2.6 खंड 5.5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

5.5 आरएफपी उन सभी बोलीदाताओं को जारी किया जाएगा, जो आरएफक्यू चरण पर अर्हक हुए हैं। अगर बोलीदाता कोई विपथन के लिए अनुरोध करता है और अधिप्राप्तिकर्ता पाता है कि विपथन उचित हैं तो अधिप्राप्तिकर्ता विपथन की सहमति देने के पूर्व उपयुक्त आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा। स्पष्टीकरण/संशोधित बोली दस्तावेज विपथन और स्पष्टीकरण की सूचना देते हुए उन सभी को वितरित किए जाएंगे; जिन्होंने आरएफपी दस्तावेज खरीदा था और उपयुक्त आयोग को भी सूचना भेजी जाएगी। अंतिम विद्युत क्रय करार अधिप्राप्तिकर्ता की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। जहां भी संशोधित बोली दस्तावेज/आशोधन जारी किए जाते हैं वहां अधिप्राप्तिकर्ता बोलीदाताओं को बोलियों की प्रस्तुति के लिए ऐसे दस्तावेजों/आशोधनों को जारी किए जाने के बाद कम से कम दो महीने का समय देगा। तथापि, सभी पूर्व-अर्हक बोलीदाताओं, जिन्होंने आरएफपी खरीदा है, की लिखित सहमति से आरएफपी दस्तावेजों में ऐसे किसी संशोधन/आशोधन के बाद आरएफपी बोलियों की प्रस्तुति के लिए कम समय दिया जा सकता है।

2.7 खंड 5.6 के उप-खंड (iv) के अधीन दूसरा पैरा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

उन मामलों, जहां कैप्टिव ईंधन स्रोत का प्रस्ताव किया जाता है, को छोड़कर, बोली मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार अथवा घरेलू बाजार, जैसा भी मामला हो, में संगत ईंधन सूचकांक (आरएफपी में यथा अभिज्ञात) के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर यथा अधिभूचित वृद्धि दर का प्रयोग बोलीदाताओं द्वारा बताए गए ऊर्जा प्रभार (अथवा खंड 4.2 में उल्लिखित मामलों में प्राप्त ऊर्जा प्रभार) में वृद्धि करने के लिए किया जाएगा। खंड 4.11(iii) के उपबंध उन मामलों, जहां अधिप्राप्तिकर्ता तटीय विद्युत स्टेशनों के लिए आयातित ईंधन का प्रयोग अधिदेशित करता है, में बोलियों के मूल्यांकन पर भी लागू होंगे। तथापि, उन मामलों, जहां बोलीदाता प्रस्तावित आपूर्ति के प्रत्येक वर्षों के लिए निश्चित ऊर्जा प्रभार बताता है, में बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा प्रभार बोली मूल्यांकन के लिए अपनाए जाएंगे।

2.8 खंड 5.6 का उप-खंड (v) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

(v) आरएफपी वह अधिकतम अवधि प्रदान करेगा, जिसके भीतर चयनित बोलीदाता को अधिप्राप्तिकर्ता के दायित्वों की पूर्ति किए जाने के अधीन विद्युत क्रय करार (पीपीए) प्रभावी होने के बाद आपूर्ति अवश्य प्रारंभ करनी होगी। यह विद्युत क्रय करार (पीपीए) लागू होने की तारीख से सामान्यतः चार वर्षों से कम नहीं होगी अगर आपूर्ति की मांग दीर्घावधिक अधिप्राप्ति के लिए की जाती है। प्रस्तावित विद्युत क्रय करार (पीपीए), जो आरएफपी दस्तावेज का भाग होता है, निर्णीत हर्जाने, जो आपूर्तियों में विलम्ब की दशा में लागू होगा, को भी निर्दिष्ट करेगा।

2.9 खंड 5.18 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

5.18 दो चरण वाली बोली प्रक्रिया में, (i) आरएफक्यू के प्रकाशन और आरएफक्यू के प्रत्युत्तर की प्रस्तुति की अंतिम तारीख के बीच न्यूनतम 45 दिनों की अवधि अनुमत्य होगी और (ii) आरएफपी जारी करने और आरएफपी बोली की प्रस्तुति की अंतिम तारीख के बीच न्यूनतम 150 दिनों की अवधि अनुमत्य होगी।

इन दिशानिर्देशों के खंड 3.2 में दिए गए अनुसार परियोजना के प्रारंभिक कार्यकलापों के संबंध में आवश्यक मानदंड पूरा करने के अधीन बोली प्रक्रिया की समय-सारणी अनुबंध-I में दर्शाई गई है। सामान्य परिस्थितियों में बोली प्रक्रिया 270 दिनों की अवधि में पूरी की जानी संभावित है।

अधिप्राप्तिकर्ता अनुबंध-I में दर्शाई गई की तुलना में विस्तारित समय-सीमा दे सकता है। तथापि, अगर बोली देने की प्रक्रिया में 730 दिनों से अधिक समय लगना संभावित हो तो खंड 5.16 के अनुसार उपयुक्त आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

2.10 खंड 5.19 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

5.19 एकल चरण बोली प्रक्रिया में आरएफक्यू/आरएफपी दस्तावेजों के जारी करने और बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बीच न्यूनतम 150 दिनों की अवधि अनुमत्य होगी। बोली प्रक्रिया की समय-सारणी अनुबंध-II में दर्शाई गई है। सामान्य परिस्थितियों में बोली प्रक्रिया 195 दिनों की अवधि में पूरी की जानी संभावित है।

अधिप्राप्तिकर्ता अनुबंध-II में दर्शाई गई की तुलना में विस्तारित समय-सीमा दे सकता है। तथापि, अगर बोली देने की प्रक्रिया में 450 दिनों से अधिक समय लगना संभावित हो तो खंड 5.16 के अनुसार उपयुक्त आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

2.11 खंड 6.11 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

6.1 विद्युत क्रय करार (पीपीए) आरएफपी बोली दस्तावेजों में अंतिम रूप दी गई शर्तों के अनुसार चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप चयनित बोलीदाता/एसपीवी के साथ (चयनित बोलीदाता द्वारा उसके अधिग्रहण के बाद) हस्ताक्षरित किया जाएगा।

इन दिशानिर्देशों के खंड 3.4 में उल्लिखित मामलों के लिए, पीपीए और अन्य परियोजना दस्तावेज आरएफपी बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के पूर्व एसपीवी और संबंधित पक्षों द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।

4003 9807-2

2.12 खंड 6.12 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

6.2 बोली प्रक्रिया की समाप्ति के बाद आरएफपी बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित मूल्यांकन समिति आरएफपी दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार बोली मूल्यांकन की अनुरूपता पर उपयुक्त प्रमाणपत्र प्रदान करेगी। अधिप्राप्तिकर्ता इन दिशानिर्देशों के अनुसार बोली प्रक्रिया की अनुरूपता पर एक प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

2.13 खंड 6.13 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

6.3 पारदर्शिता के प्रयोजनार्थ अधिप्राप्तिकर्ता पीपीए पर हस्ताक्षर होने अथवा पीपीए के लागू होने, जो भी बाद में हो, के बाद सभी बोलीदाताओं द्वारा बताए गए टैरिफ के सभी संघटकों को दर्शाते हुए बोलियां सार्वजनिक करेगा। ऐसा करते समय, केवल सफल बोलीदाता का नाम सार्वजनिक किया जाएगा और अन्य बोलीदाताओं द्वारा बताए गए टैरिफ अज्ञात रूप से सार्वजनिक किए जाएंगे। अधिप्राप्तिकर्ता खंड 6.1 के अनुसार हस्ताक्षरित पीपीए भी सार्वजनिक करेगा।

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, कम से कम दो राष्ट्रीय समाचारपत्रों में एक सूचना प्रकाशित की जाएगी और कम से कम तीस दिनों के लिए अधिप्राप्तिकर्ता की वेबसाइट पर पूर्ण ब्यौरे प्रदर्शित किए जाएंगे।

2.14 खंड 6.4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

6.4 जैसा खंड 6.2 में यथाप्रदत्त है मूल्यांकन समिति और अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों के साथ हस्ताक्षरित पीपीए अधिनियम की धारा 63 के अनुसार टैरिफ अपनाने के लिए उपयुक्त आयोग को अग्रेषित किया जाएगा।

#### अनुबंध-I

#### दो चरण बोली प्रक्रिया के लिए समय-सारणी

क्रम सं०	अगले कॉलम में कार्य होने के पूर्व पूरा किए जाने वाले कार्यकलाप	कार्य	प्रारंभिक तारीख से व्यतीत अवधि
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- भूमि: विद्युत स्टेशन की भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए।</li> <li>- पर्यावरणीय स्वीकृति : विद्युत स्टेशन के लिए तीव्र पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट उपलब्ध होनी चाहिए।</li> </ul>	आरएफक्यू का प्रकाशन।	प्रारंभिक तारीख

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ईंधन व्यवस्था : ईंधन लिकेज अथवा कोयला खान (खानों) का आवंटन, अगर लागू हो, उपलब्ध होना चाहिए।</li> <li>- जल लिकेज उपलब्ध होना चाहिए।</li> </ul>		
2		आरएफक्यू के प्रत्युत्तरों की प्रस्तुति।	45 दिन
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- भूमि : विद्युत स्टेशन की भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अधीन अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए।</li> <li>- पर्यावरणीय स्वीकृति : विद्युत स्टेशन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन प्रदान करने के उत्तरदायी संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो जाना चाहिए।</li> <li>- वन संबंधी स्वीकृति (अगर लागू हो) : विद्युत स्टेशन की भूमि के लिए वन संबंधी स्वीकृति का समुचित प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन प्रदान करने के उत्तरदायी संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</li> <li>- आंकड़ा : विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निम्नलिखित आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए : जलवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, मौसम-वैज्ञानिक, भूकम्पवैज्ञानिक आंकड़े।</li> </ul>	आरएफपी जारी करना।	75 दिन
4		बोली स्पष्टीकरण, सम्मेलन आदि	—
5		आरएफपी का अंतिम स्पष्टीकरण और संशोधन	*
6		आरएफपी बोली की प्रस्तुति	225 दिन
7		बोलियों का मूल्यांकन बनाना और आशय-पत्र (एलओआई) जारी करना	240 दिन
8	-विद्युत स्टेशन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जानी चाहिए।	पीपीए लागू होता है : निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर करना :	270 दिन

<p>-- अगर आपातस्थिति से संबंधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 के उपबंधों को लागू नहीं किया गया है तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन विद्युत स्टेशन के लिए भूमि का निर्णय घोषित हो जाना चाहिए।</p>	<p>(i) विद्युत क्रय करार, एस्करो करार, भाराक्रांति करार और यथा लागू अन्य कोई करार (अगर इन पर खंड 3.4 के अधीन हस्ताक्षर नहीं किया जा चुका हो)।</p> <p>(ii) शेयर खरीद करार और एसपीवी का हस्तान्तरण, अगर लागू हो, पर हस्ताक्षर।</p>
---	--

\* आरएफपी दस्तावेज में किसी परिवर्तन के मामले में अधिप्राप्तिकर्ता खंड 5.5 के अनुसार बोलीदाताओं को अतिरिक्त समय प्रदान करेगा।

**टिप्पणी :** यह स्पष्ट किया जाता है अगर अधिप्राप्तिकर्ता कार्य के पूर्व पूरा किए जाने के लिए अपेक्षित कार्यकलापों की प्राप्ति में विलंब के कारण बोली देने की प्रक्रिया के किसी भी कार्य के लिए विस्तारित समय देता है तो समय का ऐसा विस्तार किसी भी प्रकार इन दिशानिर्देशों से विपथन नहीं होगा। तथापि, अगर बोली प्रक्रिया में 730 दिनों से अधिक समय लगना संभावित है तो खंड 5.16 के अनुसार उपयुक्त आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

#### अनुबंध-II

#### एकल चरण बोली प्रक्रिया के लिए समय-सारणी

क्रम सं०	कार्य	प्रारंभिक तारीख से व्यतीत अवधि
1	आरएफक्यू/आरएफपी का प्रकाशन	प्रारंभिक तारीख
2	बोली स्पष्टीकरण, सम्मेलन आदि और आरएफक्यू/आरएफपी का संशोधन।	**
3	आरएफक्यू/आरएफपी बोली की प्रस्तुति।	150 दिन
4	बोलियों का मूल्यांकन और आशय पत्र जारी करना।	165 दिन
5	<p>पीपीए लागू होता है : निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर करना:</p> <p>(i) विद्युत क्रय करार, एस्करो करार, भाराक्रांति करार और अन्य कोई करार जो लागू हो (अगर इन पर खंड 3.4 के अधीन हस्ताक्षर नहीं किया जा चुका हो)।</p>	195 दिन



	(ii) शेयर क्रय करार और एसपीवी के हस्तांतरण, अगर लागू हो पर हस्ताक्षर करना।	
--	--	--

**\*\* आरएफक्यू/आरएफपी दस्तावेज में किसी परिवर्तन के मामले में अधिप्राप्तिकर्ता खंड 5.5 के अनुसार बोलीदाताओं को अतिरिक्त समय प्रदान करेगा।**

आलोक कुमार, निदेशक

**MINISTRY OF POWER  
RESOLUTION**

New Delhi, the 27th September, 2007

**Amendment to the Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for Procurement of Power by Distribution Licensees**

**No. 23/11/2004-R & R (Vol. VI).—1.** The guidelines for determination of tariff by bidding process for procurement of power by Distribution Licensees were notified under the provisions of section 63 of the Electricity Act, 2003 vide Resolution No. 23/11/2004-R & R (Vol. II) published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I, Section 1) on 19th January, 2005. These guidelines were amended vide Gazette Resolution No. 23/11/2004-R & R (Vol. IV) dated 30th March, 2006 and No. 23/11/2004-R & R (Vol. V) dated 18th August, 2006.

2. The following further amendments are hereby made in the said guidelines namely:-

2.1 The following explanation is added after sub-clause (b) of clause 2.1:

Explanation: For the purpose of these Guidelines, the term 'Procurer(s)' shall mean, as the context may require, the distribution licensee(s), or the authorised representative of the licensee(s) or a Special Purpose Vehicle (SPV) constituted for the purpose of carrying out the bidding process. SPV shall be a company established under the Indian Companies Act 1956, authorized by the distribution licensee(s) to perform all tasks for carrying out the bidding process in accordance with these Guidelines. The distribution licensee(s) may also entrust initial project preparation activities (proposed to be undertaken before completion of the bid process) to the SPV. The SPV may be transferred to the successful bidder selected pursuant to the bid process.

2.2 The first para of clause 2.4 is replaced by the following:

Procurement by more than one distribution licensee through a combined bid process shall be permitted and in such a case the Procurers shall have the option to conduct the bid process through an authorized representative. The authorized

4003 9207-3

representative may be one of the procurers or for Case 2, a special purpose vehicle (SPV) may be incorporated for such purpose. For such combined procurement, each procurer shall provide the necessary information required as per these guidelines. To ensure standardization in evaluation of bids, the payment security and other commercial terms offered to the bidders by the various procurers shall not vary. The price offered by the bidders shall also be the same for the distribution licensees inviting the bid.

2.3 Sub-clause (a) of clause 3.1(iii) is replaced by the following:

(a) For the quantum of capacity / energy to be procured, in case the same is exceeding the projected additional demand forecast for next three years following the year of expected commencement of supply proposed to be procured. Such demand forecast shall be based on the latest available (at the time of issue of RFQ) Electric Power Survey published by Central Electricity Authority. (Both for **Case 1** and **Case 2**).

2.4 Clause 3.2 is replaced by the following:

3.2 In order to ensure timely commencement of supply of electricity being procured and to convince the bidders about the irrevocable intention of the procurer, it is necessary that various project preparatory activities are completed in time. For long-term procurement from hydroelectric projects or for projects for which pre-identified sites are to be utilized (Case 2), the following project preparatory activities should be completed by the procurer, or authorized representative of the procurer, simultaneously with bid process adhering to the milestones as indicated below:-

(i) Site identification and land acquisition: If land is required to be acquired for the power station, the notification under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 should have been issued before the publication of RFQ. The notification under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 should have been issued before the issue of RFP. If the provisions of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 regarding emergency have not been applied, the Award under the Land Acquisition Act should have been declared before the PPA becomes effective.

(ii) Environmental clearance for the power station: Rapid Environmental Impact Assessment (EIA) report should be available before the publication of RFQ. Requisite proposal for the environmental clearance should have been submitted before the concerned administrative authority responsible for according final approval in the Central/ State Govt., as the case may be, before the issue of RFP. Environmental clearance should have been obtained before PPA becomes effective.

(iii) Forest Clearance (if applicable) for the land for the power station: Requisite proposal for the forest clearance should have been submitted before the concerned administrative authority responsible for according final approval in the Central/ State Govt., as the case may be, before the issue of the RFP.

(iv) Fuel Arrangements: If fuel linkage or captive coal mine(s) are to be provided, the same should be available before the publication of RFQ. In case, bidders are required to arrange fuel, the same should be clearly specified in RFQ.

(v) Water linkage : It should be available before the publication of RFQ.

(vi) Requisite Hydrological, geological, meteorological and seismological data necessary for preparation of Detailed Project Report (DPR), where applicable: These should be available before the issue of RFP. The bidder shall be free to verify geological data through his own sources, as the geological risk would lie with the project developer.

The project site shall be transferred to the successful bidder at a price to be intimated at least 15 days before the due date for submission of RFP bids.

2.5 The following clause 3.4 is inserted below clause 3.3 :

3.4 In the case of projects under Case 2 from which more than one distribution licensees located in different States intend to procure power by carrying out bidding process through a SPV, the PPA and other required project agreements (such as escrow agreement, hypothecation agreement and other project specific agreements) may be entered into between the concerned parties prior to the last date of submission of the RFP bids with the proviso that these agreements shall be effective from the date of acquisition of the SPV by the successful bidder.

2.6 Clause 5.5 is replaced by the following:

5.5 RFP shall be issued to all bidders who have qualified at the RFQ stage. In case the bidders seek any deviations and the procurer finds that the deviations are reasonable, the procurer shall obtain approval of the Appropriate Commission before agreeing to the deviations. The clarification/revised-bidding document shall be distributed to all who had bought the RFP document informing about the deviations and clarifications and an intimation shall also be sent to the Appropriate Commission. Final PPA shall also be displayed on the website of the procurer. Wherever revised bidding documents/amendments are issued, the procurer shall provide bidders at least two months after issue of such documents/amendments for submission of bids. However, a lesser time may be given for submission of RFP bids after any such revision/amendments in the RFP

documents, with the written consent of all the pre-qualified bidders who have bought the RFP.

- 2.7 The second para under sub-clause (iv) of clause 5.6 is replaced by the following:

For the purpose of bid evaluation in cases other than where a captive fuel source is offered, escalation rate, as notified by the CERC from time to time on the basis of historical data, of the relevant fuel index (as identified in the RFP) in the international market or domestic market as the case may be, shall be used for escalating the energy charge (or the derived energy charge in cases referred to in clause 4.2) quoted by the bidders. The provisions of clause 4.11(iii) would also apply to evaluation of bids in cases where the procurer mandates use of imported fuel for coastal power stations. However, in cases where the bidder quotes firm energy charges for each of the years of proposed supply, the energy charges proposed by the bidder shall be adopted for bid evaluation.

- 2.8 Sub-clause (v) of clause 5.6 becomes replaced by the following:

(v) The RFP shall provide the maximum period within which the selected bidder must commence supplies after the PPA becomes effective, subject to the obligations of the procurer being met. This shall ordinarily not be less than four years from the date of the PPA becoming effective in case supply is called for long term procurement. The model PPA which forms a part of the RFP documents shall also specify the liquidated damages that would apply in the event of delay in supplies.

- 2.9 Clause 5.18 is replaced by the following:

5.18 In the two stage bid process, (i) a minimum period of 45 days shall be allowed between the publication of RFQ and last date of submission of responses to RFQ and (ii) a minimum period of 150 days shall be allowed between the issuance of RFP and the last date of RFP bid submission.

Subject to the completion of necessary milestones in respect of project preparatory activities as given in clause 3.2 of these guidelines, the timetable for the bid process is indicated in Annexure-I. In normal circumstances, the bid process is likely to be completed in a period of 270 days.

The Procurer may give extended timeframe than indicated in the Annexure-I. However, if the bidding process is likely to take more than 730 days, approval of the Appropriate Commission shall be obtained in accordance with clause 5.16.

- 2.10 Clause 5.19 is replaced by the following:

5.19 In the single stage bid process a minimum period of 150 days shall be allowed between the issuance of RFQ/ RFP documents and the last date of bid

submission. The timetable for the bid process is indicated in Annexure-II. In normal circumstances, the bid process is likely to be completed in a period of 195 days.

The Procurer may give extended timeframe than indicated in the Annexure-II. However, if the bidding process is likely to take more than 450 days, approval of the Appropriate Commission shall be obtained in accordance with clause 5.16.

2.11 Clause 6.11 is replaced by the following:

6.1 The PPA shall be signed with the selected bidder/SPV (after its acquisition by the selected bidder) consequent to the selection process in accordance with the terms and conditions as finalized in the RFP bid documents.

For cases referred to in clause 3.4 of these Guidelines, the PPA and other project documents may be executed by the SPV and the concerned parties prior to the last date of submission of RFP bids.

2.12 Clause 6.12 is replaced by the following:

6.2 After the conclusion of bid process, the Evaluation Committee constituted for evaluation of RFP bids shall provide appropriate certification on conformity of the bid evaluation according to the provisions of the RFP document. The procurer shall provide a certificate on the conformity of the bid process to these guidelines.

2.13 Clause 6.13 is replaced by the following:

6.3 For the purpose of transparency, the procurer shall make the bids public by indicating all the components of tariff quoted by all the bidders, after signing of the PPA or PPA becoming effective, whichever is later. While doing so, only the name of the successful bidder shall be made public and details of tariffs quoted by other bidders shall be made public anonymously. The procurer shall also make public the PPA signed in accordance with clause 6.1.

For above purpose, a notice will be published in at least two national newspapers and full details shall be posted on the website of the procurer for at least thirty days.

2.14 Clause 6.14 is replaced by the following:

6.4 The signed PPA along with the certificates provided by the evaluation committee and by the procurer as provided in clause 6.2 shall be forwarded to the Appropriate Commission for adoption of tariffs in terms of Section 63 of the Act.

400392107-4

Annexure-I : Time Table for two stage bid process

Sl.No.	Activities to be completed before Event in next column takes place	Event	Elapsed Time from Zero date
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Land: Section 4 notification under the Land Acquisition Act, 1894 should have been issued for land of power station.</li> <li>- Environmental clearance: Rapid EIA report for power station should be available.</li> <li>- Fuel arrangements: Fuel linkage or allocation of coal mine(s) should be available, if applicable.</li> <li>- Water linkage should be available.</li> </ul>	Publication of RFQ	Zero date
2.		Submission of Responses of RFQ	45 days
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Land: Section 6 notification under the Land Acquisition Act, 1894 should have been issued for land of power station.</li> <li>- Environmental clearance: The proposal for environmental clearance for power station should have been submitted before the concerned authority responsible for according final approval.</li> <li>- Forest Clearance (if applicable): Requisite proposal for forest clearance for the land for the power station should have been submitted before the concerned authority responsible for according final approval.</li> <li>- Data: For preparation of DPR, following data should be available:- Hydrological, geological, meteorological, seismological data</li> </ul>	Issuance of RFP	75 days
4.		Bid clarification, conferences etc	-
5.		Final clarification and	*

Sl.No.	Activities to be completed before Event in next column takes place	Event	Elapsed Time from Zero date
		revision of RFP	
6.		RFP bid submission	225 days
7.		Evaluation of bids and issue of (Letter of Intent) LOI	240 days
8.	<p>-Environmental clearance for the power station should have been obtained.</p> <p>-If the provisions of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 regarding emergency have not been applied, the Award for the power station land under Land Acquisition Act should have been declared.</p>	<p>PPA becomes effective: Signing of Agreements:</p> <p>i) Power purchase agreement, escrow agreement, hypothecation agreement and any other agreement as applicable (if these have not been already signed under clause 3.4).</p> <p>ii) Signing of share purchase agreement and transfer of SPV, if applicable.</p>	270 days

\*In case of any change in RFP document, the procurer shall provide bidders additional time in accordance with clause 5.5.

Note : It is clarified that if the procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, such extension of time shall not in any way be deviation from the these Guidelines. However, if the bidding process is likely to take more than 730 days, approval of the Appropriate Commission shall be obtained in accordance with clause 5.16.

**Annexure-II : Time Table for single stage bid process**

Sl.No.	Event	Elapsed Time from Zero date
1.	Publication of RFQ / RFP	Zero date
2.	Bid clarification, conferences etc. & revision of RFQ/RfP	**
3.	RFQ/RFP Bid submission	150 days
4.	Evaluation of bids and issue of LOI	165 days
5.	PPA becomes effective: Signing of Agreements: i) Power purchase agreement, escrow agreement, hypothecation agreement and any other agreement as applicable (if these have not been already signed under clause 3.4). ii) Signing of share purchase agreement and transfer of SPV, if applicable.	195 days

\*\* In case of any change in RFQ/RFP document, the procurer shall provide bidders additional time in accordance with clause 5.5.

ALOK KUMAR, Director